भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1174
मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024/12अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

राज्य जैव-उत्पाद बोर्डों और एनसीओएल के बीच समझौता ज्ञापन

†**1174**. **श्री सुरेश कुमार शेटकरः**
श्री इटेला राजेंदरः
श्रीमती डी. के.अरुणाः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उर्वरकों में उपस्थित रसायन उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड और यहां तक कि कैंसर जैसे कई रोगों का स्रोत हैं और जैविक खेती 140 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य से जुड़ी थी तथा क्या नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और अन्य राज्य ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्डों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या जैविक खेती का आंदोलन महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है और भारत को विश्व का सबसे बड़ा जैविक खाद्य उत्पादक देश बनाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा क्या जैविक उत्पादों के बारे में जागरूकता है और इसके लिए बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है और जब हम इस बाजार का दोहन करके भारत की भागीदारी बढ़ाते हैं तो जैविक उत्पादों के लाभदायक व्यवसाय में हमारे किसानों की भागीदारी और उनकी आय भी बढ़ती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा/वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): जैसे जैसे खाद्य क्रृंखला में रासायनिक निविष्टियों के उपयोग द्वारा रासायनिक अवशिष्टों के गंभीर परिणामों के प्रति जागरुकता बढ़ रही है, कृषि और संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के वैकल्पिक साधनों की महत्ता बढ़ती जा रही है । जैविक खेती ऐसा ही एक विकल्प है जहां कृषि की एक ऐसी प्रणाली के तहत फसल को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना, पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक उत्तरदायित्व की पद्धति से उगाया जाता है । यह पोषक खाद्य जो जीवन शक्ति से भरपूर और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है, के उत्पादन के मिट्टी की उत्पादकता और पुनरुत्पादक क्षमता को संरक्षित रहती है ।

सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) स्थापित किया है । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ मर्यादित (NAFED), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और भारतीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा प्रवर्तित किया गया है । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) की आरंभिक प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपये है और पांचों प्रवर्तकों, प्रत्येक द्वारा 20 करोड़ रुपये का अंशदान किया गया है और इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) की स्थापना जैविक उत्पादों का एकीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, प्रापण, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाएं, विपणन और PACS/FPOs सहित इसके सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के साथ-साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की सहायता से जैविक उत्पादों के प्रोत्साहन और विकासात्मक कार्यों के लिए किया गया है । NCOL विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों द्वारा जैविक उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान कर करेगा ।

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) ने उत्तराखंड ऑर्गैनिक कमोडिटी बोर्ड (UOCB) के साथ नई दिल्ली में दिनांक 30 अगस्त, 2024 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है ।

इस सहभागिता द्वारा NCOL और UOCB साथ मिलकर उत्तराखंड राज्य में प्रमाणित जैविक उत्पादों के प्रापण में वृद्धि कर रहे हैं । इसका आरंभिक फोकस अगले रबी मौसम में UOCB से संबद्ध किसानों से गेहूं की खरीद करना है जो संवहनीय कृषि और उपभोक्ता स्वास्थ्य में सुधार की प्रतिबद्धता का द्योतक है ।

(ख): भारत में जैविक कृषि आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है और देश को जैविक कृषि के एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित किया है । भारत की विविध कृषि-जलवायु दशाएं और पारंपरिक कृषि प्रथाएं जैविक उत्पादों के उत्पादन की असीम संभावनाएं प्रदान करता है । स्वाभाविक रूप से जैविक और जंगली फसल वाले क्षेत्र अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं, जो भारत की जैविक खाद्य की बढ़ती घरेलू और निर्यात मांग को पूरा करने में सक्षम बनाता है ।

वर्ष 2023-24 में भारत ने 3.6 मिलियन मीट्रिक टन प्रमाणित जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जिसमें तिलहन, अनाज, दलहन, मसाले, फल, सब्जियां और गैर-खाद्य वस्तुएं जैसे जैविक कपास फाइबर और हर्बल उत्पाद शामिल हैं । जैविक उत्पादन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान अग्रणी राज्य हैं । भारत ने 2,61,029 मीट्रिक टन के जैविक उत्पादों का निर्यात किया जिनका मूल्य 4007.91 करोड़ रुपए (USD 494.80 मिलियन) है । प्रमुख निर्यात गंतव्य में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण पूर्वी एशिया शामिल हैं । (स्रोत: APEDA)

****